2. चाकन सिंचाई परियोजना

3. सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संशोधित अनुमान

4. मेजा आधुनिकीकरण तथा मेजा फीडर सिंचाई का संशोधित अनुमान

विद्युत

1. कोटा टीपीएस स्टेज-3

राजस्थान में लम्बित पड़े पासपोर्ट के आवेदन-पत्र

2807. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लम्बित पड़े हैं ;

(ग) 1987-88 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा प्रति वर्ष कितने पासपोर्ट जारी किए गए ; और

(घ) इस अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्र रद्द किये गये तथा उनके क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी): (क) 31-7-88 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य, जयपुर के पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट जारी करने के लिए, 9,770 आवेदन-पत्र बकाया थे।

(ख) 3 महीने से कम :	7573
3 महीने से अधिक :	1,027
6 महीने से अधिक :	1,069
1 वर्ष से अधिक :	101
(ग) 1987	10,29,795
1988 (30 जून, 1988 तक)	6,27,494
(घ) 1987 : 17	
1988 (जून, 1988 तक)	शून्य

ये सभी आवेदन-पत्र पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) की विशिष्ट उप-धाराओं के अन्तर्गत नामंजूर कर दिए गए थे जिसमें उन आधारों का उल्लेख है, जिनके आधार पर ये आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिये गए थे। मामलों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :—

1. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(क) के अंतर्गत जो इस प्रकार है कि :

"आवेदक भारत का नागरिक नहीं है"।

8. पासपोर्ट अधिनियम 1967, की धारा 6(2)(ख) के अंतर्गत जो इस प्रकार है :

"आवेदक भारत के बाहर ऐसा कार्य कर सकता है अथवा उसके द्वारा ऐसा कार्य करने की आशंका है जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता के लिए हानिकारक हो"।

2. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ग) के अंतर्गत जो इस प्रकार है :

"आवेदक का भारत से प्रस्थान, भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है अथवा होने की आशंका है"।

5. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(च) के अंतर्गत जो इस प्रकार है :

"आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में भारत में आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है।"

1. पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(1) के अंतर्गत जो इस प्रकार है :

"केन्द्रीय सरकार के विचार में आवेदक को पासपोर्ट अथवा यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी करना जनहित में नहीं होगा"।

Backlog in Seventh Fire Year Plan

2808. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a heavy blacklog in reaching the Seventh Five Year Plan target in regard to MNP designed to improve the standard of living in rural areas and reduce regional disparities in development;

(b) if so, causes for such a slow progress; and

(c) the steps being taken to improve the pace of progress to achieve the target ?

THE MINISTER-OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI) : (a) The Seventh Plan targets of different components of Minimum Needs Programme have been achieved proportionately to a satisfactory level during first three years of the Seventh Five Year Plan. However, there have been shortfalls under a few programmes in certain States.

(b) The main causes for slow progress under some of the programmes *inter-alia* are under utilisation of funds, delays in acquisition of land for infrastructure like rural roads, primary health centres and community health centres, lack of trained medical and paramedical manpower, preference of farmers for diesel pumpsets as against power energised pumpsets due to unreliability of power supply, adoption of liberal norms for construction assistance in rural housing in some States.

(c) States have been advised to utilise the earmarked MNP funds allocated for different programmes fully and to improve the pace of progress for achieving the plan targets.

Exploration of Ocean Wealth

2809. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some ocean areas are given to foreign companies for exploration of ocean wealth; and

(b) if so, the full details about the number of cases, names of the foreign companie, terms and conditions thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K.R. NARAYANAN) : (a) and (b) The exploration of ocean wealth includes a wide range of living and non-living resources. As far as the Department of Ocean Development is concerned, no ocean area is being explored with the help of foreign companies. The entire survey and exploration is being done by the Indian scientists using indigenous technology. The Ministry of Agriculture (Fisheries) and Geological Survey of India also do not get the exploration of sea resources done through foreign companies.

Some contracts, however, have been awarded by the Ministry of Petroleum and Natural Gas under the third round of offshore, exploration to foreign oil companies for exploration of hydrocarbons. The details about the number of cases, names of the foreign companies, terms and conditions thereof are given in the enclosed statement.